کہا تھا کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں یا نہیں۔
اب تو ایک کیبنیٹ منسٹر اور آ گئے ہیں
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا میکنزم
ہے کہ جو سوالات زیرو آور میں اٹھائے
جاتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا کیا اثر گورنمنٹ
پر پڑتا ہے۔ ... مداخلت ... میں
موجودگی سے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
اہم ترین سوالات یہاں اٹھائے جا رہے
ہیں اور کسی قسم کا ریسپانس نہیں
ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی میکنزم نہیں ہے
اس کا۔ کوئی ریسپانس تو ہونا چاہیئے۔
سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں وہ صرف سر
کے اوپر سے گزر جائیں اس سے کچھ حاصل
نہیں ہے۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ کوئی میکنزم
اس قسم کا ڈیولپ کرنا چاہیئے کہ گورنمنٹ
ریسپانس تو کرے ان سوالات کو جو
سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مجھے صرف
اتنا کہنا ہے۔ صرف منسٹر کے یہاں موجود
رہنے سے کیا ہوتا ہے؟]

उपाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मिनिस्टर साहब, यह जो सदन की भावनाएं हैं इन्हें आप कृपया कैबिनेट के पास पहुंचा दें क्योंकि जब पारदर्शिता, अकांटेबिलिटी और जवाबदेही की हम बात करते हैं तो ऐसे मसलों पर अवश्य कुछ-न-कुछ उस का उत्तर या जो माननीय सदस्य उस मामले को उठाते हैं उस को या सदन के सामने इस बारे में जानकारी देनी चाहिए।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : उपसभाध्यक्ष जी, आप का जो निर्देश है, उस का पालन होगा।

RE: HUNGER-STRIKE BY DOORDARSHAN AND AIR STAFF

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं शून्यकाल के माध्यम से देश भर के आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन स्टाफ की एसोसिएशन की तरफ से जो स्टाफ मैंबर्स हंगर स्ट्राइक पर 5 दिन से बैठे हुए हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर, उनके विषय में कुछ कहना चाहती हूं। 10 और 11 तारीख उन्होंने ब्लैक डे मानने का भी विचार किया है और ब्लैक डे मना रहे हैं इस विरोध में कि उनकी पे पैरिटी का मसला कई वर्षों से चल रहा है दूरदर्शन के प्रोग्राम स्टाफ, टैक्नीकल स्टाफ और इंजीनियरिंग स्टाफ में पे-पैरिटी में फर्क है, उनके पे-स्केल में फर्क है। इंजीनियरिंग स्टाफ का 1978 से पे-स्केल बढ़ा दिया गया है लेकिन प्रोग्राम स्टाफ का नहीं, जिस पर कि प्रोग्राम बनाने का सारा दारोमदार है और हमारे सरकारी मीडिया का या सरकारी घोषणाओं का और सरकारी नितियों को आगे बढ़ाने का, सरकारी माध्यम के जो इंप्लोई हैं खास तौर से प्रोग्राम स्टाफ और ट्रांसमीशिन स्टाफ के तो उनके पेस्केल नहीं बढ़ाए गए हैं।..... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : वीणा जी, ऐसे विवरण में नहीं जाइये क्योंकि कई अन्य लोग भी अपने को इससे संबंधित करना चाहते हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा : जी, मैं बिल्कुल सूत्र में ही कहूंगी। पिछले सैशन में यहां पर कई मैंबर्स मारग्रेट आल्वा और श्रीमती जयन्ती नटराजन जी ने भी यह सवाल उठाया था और मैंने भी एसोसिएट किया था। एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया था कि हां, उनकी जो पे पैरिटी की मांगें हैं वे जायज़ मांगे हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यह मामला फाइनांस मिनिस्टर के पास है जबकि यह मामला सिर्फ मिनिस्ट्री को तय करना है। आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के दो सौ केन्द्रों में करीब 8 सौ के करीब पोस्ट्स हैं..... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : पूरी मांगें यहां पर नहीं रखिए। देखिए आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है और वह इसे देखेगी। अब इसके उपरांत श्री सतीश प्रधान।

श्रीमती वीणा वर्मा : सर, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगी। मैं कहना चाहती हूं कि उनकी जो पोस्ट्स हैं उनको भरा जाए। दूसरा प्रोग्राम स्टाफ ....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : वे सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप कह रही हैं और जब वह

उत्तर देंगे तब वह आपको पूरा बतायेंगे।....(व्यवधान)

श्रीमती वीणा वर्मा : सर, जैसा उत्तर मांगते हैं वैसा उत्तर तो जीरो आवर का आता नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा (कर्णाटक): लास्ट सेशन में भी यह मामला उठाया था। कहा गया कि डिसकस हो रहा है। हम लोक कुछ करेंगे। ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : इसी वजह से सिकन्दर बख्त साहब ने कहा कि रेसपांड करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए....(व्यवधान)

श्रीमती वीणा वर्मा : कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भी कई बार यह मामला आया है। ....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : इसी वजह से सिकन्दर बख्त साहब ने वही सवाल उठाया कि रेसपां करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अब श्री सतीश प्रधान। आप जरा संक्षेप में कहिए।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा और एक मिनट के अंदर बैठ जाऊंगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि दूरदर्शन और अकाशवाणी के आफिसर और स्टाफ दिल्ली में आकाशवारी भवन के सामने 6 दिन से अनशन पर बैठे हैं और तीन दिन हुए दिल्ली के अलावा मुंबई, कटक, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कलकत्ता और शिलांग जगहों पर उन्होंने अनशन शुरू किया है।....(व्यवधान) और बाकी सब कर्मचारी लोग वहां पूरे दिन के लिए उनके साथ बैठ रहे हैं। बहुत चिंताजनक बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने 27 अगस्त को क्वश्चन नं० 367 का जवाब देते समय मान लिया था कि ये मांगे बराबर हैं और हम उन्हें पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक इस विषय में कुछ नहीं किया गया और अब उनके अनशन पर बैठने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : आपकी मांग है, वह उसको जल्दी करेगी।

श्री सतीश प्रधान : मुझे कहना है कि तुरन्त इस विषय में वह निर्णय करे और ऐसा कोई मौका नहीं मिले कि यहां कुछ गलत हो जाए और कोई आपत्तिजनक परिस्थिति खड़ी हो। यह मेरा कहना है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Shri Nilotpal Basu. Please take not more than half a minute.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, the issue is very simple. Now the question of pay-parity is with the Finance Ministry; Information & Broadcasting Ministry has gone on record on the floor of the House that this demand is justified, Finance Ministry is taking umbrage behind the logic that this will be referred to the Pay Commission. The Pay Commission has also made it very clear that they cannot settle the past arrears. Therefore, we urge upon the Government that it is a question of the health of the information and broadcasting industry and the Government should concede their demands and settle the issues.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, ऑल इंडिया रेडियों और दूरदर्शन के प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन की जो मांग है, वह बिल्कुल जायज है और मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूं।

मान्यवर, इंजीनियर्स का जो पेस्केल पर कोई उयान नहीं दिया जा रहा है। यह मिनिस्टरी आफ फाइनेन्स से संबंधित मामला है। यहां तक आई एण्ड बी० का काम है, उस मिनिस्टरी द्वारा इस संबंध में अपने व्यूज मिनिस्टरी आफ फाइनेन्स को भेजे जा चुके हैं। मैं सोचता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो डी०डी०जी० और डी०जी० की पोस्ट है, वह आई०ए०एस० अधिकारियों के द्वारा भरी गई हैं, यदि यह पोस्टें जो इस मंत्रालय के सीनियर संबद्ध अधिकारी हैं उनके द्वारा भरी जाए तो मैं समझता हूं कि प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन के लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यह जो प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन के लोग एक सप्ताह से आकाशवाणी के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी जायज मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, उनकी मांगों पर सरकार समय रहते उचित कदम उठाए । धन्यवाद।

RE: SOCIAL UNREST IN MANIPUR DUE TO VARIOUS UNATTENDED AND UNRESOLVED PROBLEMS

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Sir, this is a question of nation-